



**अध्याय II**  
**वाणिज्य-कर**



## अध्याय II : वाणिज्य-कर

### 2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर विभाग मुख्य रूप से विभिन्न अधिनियमों के तहत कर प्रशासन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जैसा कि, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017; बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948; बिहार पेशा कर अधिनियम, 2011; बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005; केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948; बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007; बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988; बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य-कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को प्रशासन, अपील और लेखापरीक्षा (प्रत्येक नौ प्रमंडल<sup>1</sup>), जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

### 2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वाणिज्य-कर विभाग के 90 इकाइयों में से 17 इकाइयों के अभिलेखों का नमूना-जाँच की, जिसमें 242 मामलों में सन्निहित ₹ 35.21 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो निम्न श्रेणियाँ के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1  
लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
<b>क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर</b>			
1.	कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	02	110.91
2.	आवर्त का छिपाव किया जाना	29	197.69
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	30	683.36
4.	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	01	11.21
5.	कर की रियायती दर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	07	130.18
6.	कर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	02	1.63
7.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	25	151.01
8.	कर का गलत दर लगाया जाना	14	436.07
9.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	02	8.21
10.	संग्रहण में गलती से कर अधिक संग्रह के लिए जुर्माना नहीं लगाना	13	72.83
11.	कर का आरोपण नहीं करना	04	77.19
12.	अन्य मामले	38	111.18
<b>कुल</b>		<b>167</b>	<b>1,991.47</b>

<sup>1</sup> भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना मध्य, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

क्र० सं०	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
<b>ख: प्रवेश कर</b>			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	17	587.87
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	04	23.72
3.	अन्य मामले	00	00
<b>कुल</b>		<b>21</b>	<b>611.59</b>
<b>ग: माल एवं सेवा कर</b>			
1.	माल एवं सेवा कर का नहीं/कम आरोपण किया जाना	54	917.89
<b>कुल</b>		<b>54</b>	<b>917.89</b>
<b>कुल योग</b>		<b>242</b>	<b>3,520.95</b>

वर्ष 2021-22 के दौरान, विभाग ने 122 मामलों में ₹ 11.65 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 44 मामलों में ₹ 0.44 करोड़ की वसूली की, जो कि 2021-22 के दौरान इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2021-22 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त हैं (जून 2023)।

### 2.3 “माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा”

#### 2.3.1 परिचय

माल एवं सेवा कर की शुरुआत ने, केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया गया है। माल एवं सेवा कर, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। केंद्र और राज्य एक साथ एक साझा कर आधार पर माल एवं सेवा कर लगाते हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर/केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर, राज्य अंतर्गत आपूर्ति पर लगाया जाता है और एकीकृत माल एवं सेवा कर अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, की धारा 59, माल एवं सेवा कर को स्व-मूल्यांकन आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। माल एवं सेवा कर रिटर्न को सामान्य माल एवं सेवा कर पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन अवश्य दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देय होगा। यहाँ तक कि अगर व्यवसाय पर किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न दाखिल करना होगा। आगे, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61, सह पठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है। करदाताओं को विसंगतियों को सूचित कर सकता है और स्पष्टीकरण माँग कर सकता है।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र तथा इस नई कर व्यवस्था में वाणिज्य-कर विभाग, बिहार की निगरानी व्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया था।

### 2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा माल एवं सेवा कर शासन के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में उन्मुख थी। “माल एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी” की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- i. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था और करदाताओं द्वारा इसका विधिवत रूप से पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या अंचलों की संवीक्षा प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

### 2.3.3 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग्स पर प्रकाश डाला था। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल के डोमेन में 15 विचलनों के एक सेट की पहचान की गई थी। इन विचलनों का एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा<sup>2</sup> के माध्यम से अनुपालन किया गया था, जिसके तहत इन विचलनों को राज्य के संबंधित विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं (अंचलों) को सूचित किया गया था और चिन्हित विचलनों पर अंचलों द्वारा की गई कार्रवाई का पता बिना क्षेत्र दौरे के किया गया था।

**केंद्रीकृत लेखापरीक्षा** को क्षेत्राधिकार अंचलों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरे के दौरान एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरा किया गया था। वाणिज्य कर विभाग, बिहार द्वारा प्रदान किए गए एकल हस्ताक्षरित उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके माल एवं सेवा कर पोर्टल (बैक-एंड सिस्टम) के माध्यम से रिटर्न और संबंधित संलग्नक और जानकारी प्राप्त की गई थी, ताकि करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्यों की जाँच की जा सके।

**विस्तृत लेखापरीक्षा** में संबंधित क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं से संबंधित अभिलेखों जैसे विपत्रों की उपलब्धता शामिल थे। इसके अलावा, चयनित अंचलों में रिटर्न की जाँच जैसे विभागीय संगठनों के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित अंचलों के निरीक्षण कार्यों की लेखापरीक्षा अवधि 2017-18 से 2020-21 थी। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया है। क्षेत्र लेखापरीक्षा, मार्च 2022 से जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 7 फरवरी 2022 को राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना

<sup>2</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाता के बारीक अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण संबंधित बही खाते, विपत्र, इकरारनामे आदि शामिल नहीं थे।

चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार के साथ 10 जनवरी 2023 को बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। राज्य कर आयुक्त, बिहार द्वारा बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए गए विचारों और प्रारूप प्रतिवेदन के लिखित जवाबों को संबंधित कंडिकाओं में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के साथ-साथ ही वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट जिसमें क्षेत्र दौर शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की जाँच हेतु क्षेत्र दौर शामिल थे; और अंचलों के अनुपालन कार्यों की मूल्यांकन के लिए अंचलों का एक नमूना।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

#### (i) भाग I-अंचलो की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए तीन से अधिक चयनित करदाताओं के क्षेत्राधिकार वाले नौ अंचलों<sup>3</sup> को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए अंचलों के नमूने के रूप में माना गया था।

#### (ii) भाग II-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन और रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 471 करदाताओं का चयन किया गया था और 423 विचलनों के बारे में राज्य कर प्राधिकारियों को सूचित किया गया था और अभिज्ञात विचलनों पर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया था।

#### (iii) भाग III-विस्तृत लेखापरीक्षा

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन के मूल्यांकन के लिए अंचलों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों की उपलब्धता द्वारा किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदंडों जैसे कि अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता की सकल आवर्त की तुलना में असमान छूट वाले आवर्त और अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल के आधार पर किया गया था।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 37 अंचलों<sup>4</sup> से संबंधित 100 करदाताओं में बड़े, मध्यम और छोटे करदाता<sup>5</sup> शामिल थे।

<sup>3</sup> औरंगाबाद, भभुआ, गया, कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।

<sup>4</sup> औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, दानापुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, कदमकुआँ, खगड़िया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, नवादा, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल एवं तेघरा।

<sup>5</sup> बड़े करदाता- 63, मध्यम करदाता- 28 और छोटे करदाता- 9।

### 2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं।

**तालिका 1**  
**मानदंडों का स्रोत**

क्र० सं०	विषय	अधिनियम और नियम
1.	आरोपण एवं संग्रहण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9।
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 (3)।
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना और उसका उपभोग	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के तहत धारा 6 से 21; अध्याय V के तहत नियम 36 से 45।
4.	पंजीकरण	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 22 से 25; बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 8 से 26।
5.	आपूर्ति	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 7 और 8. बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची I, II और III।
6.	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 से 13।
7.	आपूर्ति का समय	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 से 14।
8.	आपूर्ति का मूल्यांकन	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 27 से 34।
9.	कर का भुगतान	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53; बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के अध्याय IX के तहत नियम 85 से 88A।
10.	माल एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करना	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47; अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81। बिहार माल एवं सेवा कर नियमों का भाग-बी (रिटर्न का प्रारूप)।
11.	शून्य-रेटेड आपूर्ति	एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 8।
12.	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61, 62, 65 और 66; बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102 तक।

इसके अलावा, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड/राज्य कर विभाग द्वारा रिटर्न दाखिल करने, विभिन्न रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उपयोग करने, रिटर्न की जाँच और कर अनुपालन की निगरानी आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ और परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थे।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

37 अंचलों में की गई लेखापरीक्षा ने प्रणालीगत और अनुपालन दोनों मुद्दों को सामने लाया है। जबकि प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को संबोधित करते हैं, अनुपालन मुद्दे अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन से संबंधित हैं। यह देखते हुए कि यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विभाग के निरीक्षण तंत्र का मूल्यांकन करने की दिशा में उन्मुख था, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी
- कर भुगतान पर निगरानी
- अन्य निगरानी कार्य

### 2.3.6 रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा किए गए व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से एक पूर्ण और सही रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है जो एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता और निर्धारित समय के भीतर भुगतान किए गए करों की विधिवत घोषणा करता है। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल की निगरानी अधिक महत्व प्राप्त करता है क्योंकि रिटर्न करदाताओं और उनकी संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का पहला तरीका है।

#### 2.3.6.1 रिटर्न दाखिल में रुझान

अगस्त 2023 तक मासिक जीएसटीआर-3 बी और जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की समग्र प्रवृत्ति नीचे तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2

#### जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का रुझान

वित्तीय वर्ष	दाखिल किए जाने वाले रिटर्नों की संख्या		नियत तिथि तक दाखिल रिटर्नों की संख्या		नियत तारीख के बाद दाखिल रिटर्नों की संख्या		कुल दाखिल रिटर्न		रिटर्न दाखिल किए जाने का प्रतिशत		नियत तिथि तक दाखिल रिटर्न का प्रतिशत	
	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2017-18	19,62,881	12,92,941	9,09,610	7,77,820	8,54,866	2,75,185	17,64,476	10,53,005	90	81	52	74
2018-19	33,13,678	21,22,064	17,48,751	5,24,212	11,21,273	9,73,672	28,70,024	14,97,884	87	71	61	35
2019-20	38,54,767	24,57,947	20,60,332	5,59,667	13,95,134	11,54,743	32,99,465	17,14,410	86	70	62	33
2020-21	39,27,314	31,64,279	18,15,850	7,29,602	16,85,689	13,72,662	35,01,539	21,02,264	89	66	52	35
2021-22	37,70,781	37,70,781	22,80,785	10,17,872	11,35,729	22,02,926	34,16,514	32,20,798	91	85	67	32

(स्रोत: माल एवं सेवा कर वेबसाइट <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics>)

उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि माल एवं सेवा कर कार्यान्वयन की शुरुआत से ही कर रिटर्न दाखिल करने में विलंब हुई है, जीएसटीआर -3 बी की तुलना में जीएसटीआर -1 दाखिल करने में और भी अधिक देरी हुई है। जीएसटीआर-1 को रिटर्न दाखिल किए जाने का प्रतिशतता संबंधित जीएसटीआर-3बी के दाखिल किए जाने के प्रतिशतता की तुलना में कम था। नियत तारीख तक दाखिल जीएसटीआर-1 पहले साल के 74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में केवल 32 प्रतिशत रह गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के अनुपालन में अंतर से जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न के बीच आवर्त, कर देनदारी और उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी कर सूचनाओं में अंतर बढ़ सकता है, जिससे विभाग के अनुपालन कार्य अधिक जटिल और बोझिल हो सकते हैं।

#### 2.3.6.2 रिटर्न दाखिल पर कमजोर निगरानी तंत्र

नौ अंचलों के नमूनों में से छह अंचलों<sup>6</sup>, ने वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी, तीन अंचलों<sup>7</sup> ने वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी और तीन अंचलों<sup>8</sup> ने वर्ष 2020-21 के लिए ऐसी जानकारी नहीं दी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा उपर्युक्त अवधियों के लिए इन अंचलों में रिटर्न दाखिल किए जाने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सका।

<sup>6</sup> औरंगाबाद, गया, कदमकुआँ, पटना मध्य, पटना उत्तरी और सासाराम।

<sup>7</sup> औरंगाबाद, गया और पटना मध्य।

<sup>8</sup> पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।



### 2.3.6.3 विलंब से रिटर्न दाखिल करने वालों और रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई की कमी

माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 सपटित माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 68 के अनुसार प्रपत्र जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करने के लिए प्रावधान है, जिसमें करदाता द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने पर, पंद्रह दिनों के अंदर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी संबंधित सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और प्रपत्र एएसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकता है। रिटर्न दाखिल करना, कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों के लिए नियत तिथि समान है, जिससे रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के मामले में कर/जुर्माना का भुगतान नहीं किए जाने का जोखिम होता है।

अंचल लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2018-19 के दौरान पहचाने गए 2,527 रिटर्न दाखिल नहीं किये जाने के मामलों में से केवल 528 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था; 2019-20 के दौरान पहचान किए गए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के 8,441 मामलों में से, केवल 3,172 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था और इसी प्रकार 2020-21 के दौरान पहचान किए गए रिटर्न दाखिल नहीं किए जाने के 14,931 मामलों में से, केवल 10,982 मामलों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब आप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

### 2.3.6.4 रिटर्न की संवीक्षा की धीमी गति

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा, सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है ताकि रिटर्न की शुद्धता की पुष्टि की जा सके, और रिटर्न में प्रदर्शित किसी भी विसंगतियों या असंगतता पर उपयुक्त कार्रवाई किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए नामित सक्षम अधिकारी, अंचल अधिकारी है। इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि यदि कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं, तो उनका स्पष्टीकरण मांगने के लिए करदाता को पत्राचार किया जाएगा।

सीबीआईसी ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के रिटर्न की संवीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया परिचालित (मार्च 2022) की थी। हालाँकि, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार ने माल एवं सेवा कर रिटर्न की संवीक्षा के संबंध में ऐसी कोई विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया या विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किया। विभाग ने दोहराया कि जाँच तंत्र की निगरानी माल एवं सेवा कर प्रकोष्ठ द्वारा कुछ निश्चित मानदंडों<sup>9</sup> के आधार पर की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नौ नमूना जाँचित अंचलों<sup>10</sup> में संवीक्षा प्रणाली में कमी थी क्योंकि 2017-18 से 2020-21 के दौरान सक्षम अधिकारियों द्वारा 6,760 करदाताओं से संबंधित 53,623 माल एवं सेवा कर रिटर्न की संवीक्षा की गई थी, यद्यपि केवल जीएसटीआर-3बी में मासिक रिटर्न एवं जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न पर विचार करने पर 6,760 करदाताओं में से कम से कम 3,31,240 रिटर्न दाखिल किया गया था। इस प्रकार, 2017-18 से 2020-21

<sup>9</sup> जीएसटीएन द्वारा प्रेषित रेड प्लैग प्रतिवेदन, बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स प्रतिवेदन, और अन्य मापदंड जैसे आवर्त, देयता, नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर द्वारा जारी ई-वे बिल आदि।

<sup>10</sup> औरंगाबाद, भभुआ, गया, कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पटना विशेष और सासाराम।

के दौरान, 16 प्रतिशत रिटर्न की संवीक्षा की गई, जो विभाग में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया/निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण था। इसके अलावा, औरंगाबाद अंचल ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान की गई संवीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। संवीक्षा के लिए इन रिटर्न/करदाताओं का चयन किस आधार पर किया गया था, इसका आधार (जोखिम आधारित दृष्टिकोण) भी स्पष्ट नहीं है।

**अनुशंसा 1: विभाग रिटर्न की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया या विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इस तरह की मानक संचालन प्रक्रिया में संवीक्षा के लिए चयन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण, जो उपलब्ध जनशक्ति संसाधनों के अनुरूप है, संवीक्षा करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं और दस्तावेजों के रख रखाव और संवीक्षा के संचालन के लिए समय सीमा की पहचान की जानी चाहिए।**

### 2.3.6.5 कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलम्ब

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का, ऐसी अवधि के लिए एसी आवृत्ति पर और इस तरह से लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(13) "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या इसके तहत बनये गये नियमों या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये या प्रस्तुत किये गये अभिलेख रिटर्न और अन्य संधारित दस्तावेजों की संवीक्षा के रूप में परिभाषित की जानी है या विभाग ने घोषित आवर्त, भुगतान किये गये कर, दावा किये गये रिफंड और प्राप्त किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए या इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाना है।

विभाग ने मई 2022 में, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 1,717 करदाताओं का आंतरिक लेखापरीक्षा आरंभ किया था। लेखापरीक्षा ने, विभाग से आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति के संबंध में जानकारी की मांग की (अक्टूबर 2022)। हालाँकि, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

**अनुशंसा 2: विभाग को धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए वसूली की जा सके। ऐसे लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के चयन का आधार/मानदंड भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया चाहिए।**

### 2.3.7 कर भुगतान पर निगरानी

अनुपालन जोखिम प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जो सक्रिय कार्रवाई की मांग करती है। रिटर्न दाखिल करने और कर प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, न केवल विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान पर निगरानी बनाए रखी जा सकती है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा गैर-हस्तक्षेप और बेहतर लक्षित भी हो सकता है। लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आगामी कांडिका में चर्चा की गई है:

#### 2.3.7.1 माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियां— केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित माल एवं सेवा कर रिटर्न आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल माल एवं सेवा कर

रिटर्न के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 15 मापदंडों के एक सेट पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो डोमेन में वर्गीकृत किया जा सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर भुगतान।

13 निर्धारित माल एवं सेवा कर रिटर्न<sup>11</sup> में से, निम्नलिखित मूल रिटर्न जो सामान्य करदाताओं पर लागू होते हैं, माल एवं सेवा कर रिटर्न और डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किए गए थे:

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल है।
- जीएसटीआर-3बी: अधिनियम की धारा 39 (1) में सन्निहित करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट का मासिक सारांश रिटर्न दाखिल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को प्रतिबिम्बित करता है।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-8: अक्टूबर 2018 में पेश किए गए माल एवं सेवा कर के तहत स्रोत पर एकत्र कर में कटौती करने के लिए आवश्यक ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा मासिक रिटर्न दाखिल किया जाना है।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक, टीडीएस कटौतीकर्ता/टीडीएस संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाना है। इस दस्तावेज में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर और एकीकृत माल एवं सेवा कर) के तहत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण और इसके लिए आवर्त और लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का आवर्त करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा प्रपत्र। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाशोधन विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: एक प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक तंत्र जनित विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेन का विवरण शामिल है, जो उनके फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित किया गया है। जीएसटीआर-6 से इनपुट सेवा वितरक, काउंटर पार्टी द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और प्रवेश बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ है।

<sup>11</sup> जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन स्कीम के तहत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस कटौती करने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स संचालक), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन धारक और रिफंड का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08 एवं आईटीसी-04 (कार्य-कर्ता को भेजे गए/प्राप्त किये गये सामान के विवरण के बारे में विवरण प्रधान/कार्य-कर्ता द्वारा दाखिल किया जाना है)।

15 पहचाने गए मापदंडों और देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा (यानी केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना) पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल राज्य डेटा विश्लेषण को नीचे तालिका 3 में संक्षेपित किया गया है।

**तालिका 3**

**पैन स्टेट डेटा विश्लेषण का सारांश**

क्र. सं.	मापदंड	उपयोग किया गया कलनविधि	विचलनों की संख्या	राशि (करोड़ में)
<b>कार्यक्षेत्र : इनपुट टैक्स क्रेडिट</b>				
1.	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के मध्य बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना सभी संशोधनों के साथ घरेलू आपूर्ति पर अर्जित के साथ तालिका-4ए(5) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी, जिसमें तालिका-4बी(2) को छोड़कर शामिल किया गया था, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी से हटा दिया गया।	50	88.08
2.	रिवर्स चार्ज मैकेनिजम पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी के भीतर जाँच सीमित था, तालिका-3.1(डी) में दिए गए कर की तुलना में तालिका-4ए(2) और 4ए(3) में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में कर का निर्वहन किया गया था।	50	17.73
3.	भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिजम पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9, तालिका-4जी (देय कर) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ की गई थी। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज मैकेनिजम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2) और 4ए(3) से की गई।	18	2.53
4.	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	जीएसटीआर-9, तालिका-6जी या जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका-5ए, तालिका 8ए और तालिका-9ए के योग से की गई।	25	3.52
5.	गलत इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट रिवर्सल	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9, तालिका-7बी/7एच की तुलना उनके जीएसटीआर-6 रिटर्न के तालिका-8ए (केवल नकारात्मक आँकड़े) और तालिका-9ए (केवल नकारात्मक आँकड़े) के योग से की गई थी।	02	0.00
6.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-12एफ में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-13 में दिए गए कारणों की जाँच।	25	24.59
7.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	जीएसटीआर-9सी, तालिका-14टी में सकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-15 में दिए गए कारणों की जाँच।	25	349.66
<b>कार्यक्षेत्र : कर भुगतान</b>				
8.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-5आर में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-6 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	6,842.12
9.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-7जी में नकारात्मक आँकड़े और बेमेल के लिए तालिका-8 में दिए गए कारणों की जाँच।	34	395.64
10.	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	जीएसटीआर-9सी, तालिका-9आर में नकारात्मक आँकड़ा और बेमेल के लिए तालिका-10 में दिए गए कारणों की जाँच।	50	29.05

11.	अभुक्त कर देयता	जीएसटीआर-1 (तालिका-4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका-4एन, 10 और 11) के बीच अधिकतम कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किए गए कर विवरणों से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ चुकाए गए जीएसटीआर-3बी कर भुगतान की तुलना जीएसटीआर-1 देनदारी से की गई। जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	25	163.48
12.	कंपोजिशन करदाताओं ने ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8, 01.10.2018 से प्रभावी हो गया जब स्रोत पर कर संग्रह प्रावधान प्रभावी हो गए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	16	0.00
13.	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	करदाताओं जिसने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, दशार्ता है की कर निर्वहन के बिना करदाताओं ने कारोबार किया।	25	1.60
14.	विलम्ब भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में देरी पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गई है।	25	6.74
15.	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले	जिन करदाताओं ने लगातार छह से अधिक कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल करना बंद कर दिया और इसलिए उनके पंजीकरण को रद्द करने के लिए उत्तरदायी थे, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया।	3	0.00

### 2.3.7.2 विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 15 मापदंडों में 423 विचलनों/ विसंगतियों के मामलों के नमूने का चयन किया और करदाता के अभिलेखों की आगे जाँच किए बिना मार्च से अप्रैल 2022 के दौरान संबंधित अंचलों को लेखापरीक्षा पृच्छा जारी किए गए। इन मामलों में पहचान किए गए विचलनों/बेमेलों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करने का लेखापरीक्षा की जाँच सीमित थी। मार्च 2023 के अनुसार 62 विसंगतियों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त किया जाना था, जो नीचे तालिका 4 में संक्षेप में ₹ 98.08 करोड़ के संभावित अनावरण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती हैं।

**तालिका 4**  
**जवाब अप्राप्त**

लेखापरीक्षा आयाम	जारी लेखापरीक्षा पृच्छा		विभाग का जवाब अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	88.08	3	3.65	6	2
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	50	17.73	5	2.62	10	15
भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	18	2.53	0	0.00	0	0
जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	25	24.59	8	8.56	32	35
जीएसटीआर-9सी की तालिका-14टी में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	25	349.66	2	32.26	8	9
जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त	50	6,842.12	1	10.10	2	0
जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	34	395.64	3	9.60	9	1
जीएसटीआर-9सी की तालिका-9 आर में असमाशोधित कर देयता	50	29.05	12	6.17	24	11
इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	25	3.52	1	0.11	4	3

लेखापरीक्षा आयाम	जारी लेखापरीक्षा पृच्छा		विभाग का जवाब अप्राप्त		प्रतिशतता	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	25	6.74	9	2.78	32	43
अभुक्त कर देयता	25	163.48	3	21.70	12	13
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 या 2ए उपलब्ध है	25	1.60	8	0.53	28	33
कंपोजिशन करदाताओं ने ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया	16	0.00	5	0.00	31	0
इनपुट सेवा वितरक रिवर्सल	2	0.00	0	0.00	0	0
रिटर्न दाखिल न करने वाले	3	0.00	2	0.00	67	0
<b>कुल</b>	<b>423</b>	<b>7,924.74</b>	<b>62</b>	<b>98.08</b>	<b>265</b>	<b>165</b>

यह देखते हुए कि विसंगतियों को अनुपालन विचलन में परिवर्तित करने की समग्र दर महत्वपूर्ण है, जैसा कि अगले कंडिका में बताया गया है, विभाग को प्राथमिकता के रूप में इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट 2.1 में सूचीबद्ध है और शीर्ष 10 मामले नीचे तालिका 5 में दिए गए हैं।

#### तालिका 5

#### शीर्ष 10 मामले जहाँ प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि
1.	10 XXXXXXXXXXXX 2Z0	पटना सिटी पूर्वी	27.73
2.	10 XXXXXXXXXXXX 1ZY	हाजीपुर	11.94
3.	10 XXXXXXXXXXXX 1Z2	कटिहार	10.10
4.	10 XXXXXXXXXXXX 2Z0	पटना विशेष	8.08
5.	10 XXXXXXXXXXXX 1ZL	पटना मध्य	4.53
6.	10 XXXXXXXXXXXX 1ZP	बगहा	3.95
7.	10 XXXXXXXXXXXX 1ZF	औरंगाबाद	3.16
8.	10 XXXXXXXXXXXX 1ZK	कटिहार	3.01
9.	10 XXXXXXXXXXXX 1Z9	कटिहार	2.63
10.	10 XXXXXXXXXXXX 1Z2	फारबिसगंज	2.03

**अनुशंसा 3:** विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 62 विसंगतियों और विचलनों का अनुसरण कर सकता है, जिनके लिए प्रतिक्रिया प्रदान नहीं किए गए हैं।

#### 2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा पृच्छाओं के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में अनुवादित 15 पहचाने गए मापदंडों को नीचे दी गई तालिका 6 में संक्षिप्त किया गया है जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में वर्णित है।





के लिए फॉर्म एसएमटी-10 में विसगतियाँ बताते हुए करदाताओं को नोटिस जारी किया और ₹ 1,347.39 करोड़ से जुड़े 55 मामलों में संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया। प्रत्येक आयाम के अंतर्गत शीर्ष मामला नीचे तालिका 7 में दी गई है।

**तालिका 7**  
**केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के प्रत्येक आयाम के लिए शीर्ष मामला**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	अंचल	बेमेल राशि	की गई कार्रवाई
1	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZM	मोतिहारी	6.02	एसएमटी-10 जारी
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZT	शाहाबाद	1.06	कार्रवाई शुरू
3	भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZR	बक्सर	0.17	डीआरसी-01 जारी
4	जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट	10XXXXXXXXXX1ZG	पटना विशेष	2.79	कार्यवाही प्रगति पर है
5	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त	10XXXXXXXXXX2ZD	पटना विशेष	977.72	कार्यवाही प्रगति पर है
6	जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर योग्य आवर्त	10XXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	96.23	नोटिस जारी
7	जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता	10XXXXXXXXXX2ZS	पटना दक्षिणी	1.59	डीआरसी-01 जारी
8	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	10XXXXXXXXXX1ZS	पाटलिपुत्र	0.61	डीआरसी-01 जारी
9	विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	10XXXXXXXXXX1ZB	पटना दक्षिणी	0.45	डीआरसी-01 जारी
10	अभुक्त कर देयता	10XXXXXXXXXX1ZQ	पूर्णिया	39.48	डीआरसी-07 जारी
11	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	10XXXXXXXXXX1ZZ	पटना विशेष	0.53	कार्यवाही प्रगति पर है

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के तहत आयाम-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे वर्णित हैं:

**(I) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट**

12 अंचलों में, 26 करदाताओं ने, जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 761.76 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए उनके जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 720.03 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था।

जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट घोषित और कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्वयं-घोषित किया जाता है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से प्रासंगिक डेटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना उसके सभी संशोधनों के साथ और तालिका-4ए(5)<sup>12</sup> में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स

<sup>12</sup> अन्य सभी पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट।



क्रेडिट की तुलना करने के लिए की गई थी तालिका-4बी(2)<sup>13</sup> में किए गए उलटफेर को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2017-18 में 12 अंचलों<sup>14</sup> के अधीन 26 करदाताओं ने, जीएसटीआर-3बी के द्वारा ₹ 761.76 करोड़<sup>15</sup> के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया था, जबकि जीएसटीआर-2ए में मात्र ₹ 720.03 करोड़ उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 41.73 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जान पर (मार्च 2022), पर विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि चार अंचलों<sup>16</sup> के पाँच मामलों में नोटिस/एसएमटी-10/डीआरसी-01 जारी किया गया था, चार अंचलों<sup>17</sup> के 12 मामलों में तथ्य को आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, तीन अंचलों<sup>18</sup> के चार मामलों में डीआरसी-07 जारी किए गए थे, चार अंचलों<sup>19</sup> के पाँच मामलों में विभाग के जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि वे पूर्ण, समावेशी नहीं थे या विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

मोतिहारी अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZM) ने जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) में ₹ 7.32 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपभोग किया था (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(5) से तालिका-4बी(2) में उलटफेर को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया था। जबकि सभी संशोधित सहित जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 1.30 करोड़ उपलब्ध थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.02 करोड़ की प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की विसंगति हुई। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग ने कहा कि एसएमटी-10 और अनुस्मारक जारी किए गए थे।

**अनुशंसा 4: विभाग को इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन को प्रारंभ करना चाहिए एवं तदनुसार राजस्व के हानि का वसूली की जा सकती है।**

## (II) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट

**11 अंचलों के, 22 करदाताओं ने, वर्ष 2017-18 के में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।**

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक प्रतिवेदन है जिसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बार पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाता है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों और विशेष आर्थिक

<sup>13</sup> अन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल।

<sup>14</sup> बाढ़, बक्सर, गाँधी मैदान, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, सासाराम और सिवान।

<sup>15</sup> ₹ 736.19 करोड़ (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4ए(2) में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया) + ₹ 27.51 करोड़ (इनपुट टैक्स क्रेडिट ने जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी में लिया) - ₹ 1.94 करोड़ (जीएसटीआर-3बी की तालिका-4बी(2) में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल)।

<sup>16</sup> बक्सर, मोतिहारी, पटना सिटी पूर्वी और सिवान।

<sup>17</sup> गाँधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना दक्षिणी और पटना विशेष।

<sup>18</sup> बाढ़, पटना उत्तरी और पाटलिपुत्र।

<sup>19</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना विशेष और सासाराम।

क्षेत्र डेवलपर्स सहित नियमित करदाता थे। करदाताओं द्वारा खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए रिफंड या बनाई गई माँग आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर-3बी और वार्षिक प्रतिवेदन (जीएसटीआर-9) से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी)<sup>20</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतानों की तुलना जीएसटीआर-9, तालिका-6सी<sup>21</sup>, 6डी<sup>22</sup> और 6एफ<sup>23</sup> में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से करने के लिए अपनाई गई पद्धति थी। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी के अंतर्गत चेक सीमित थे, जहाँ जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी) में दिए गए कर की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2)<sup>24</sup> और 4ए(3)<sup>25</sup> के हिस्से का लाभ उठाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>26</sup> के 22 करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 7.28 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया था जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि सिवान अंचल के दो मामलों में राशि वसूल की गई थी, सात अंचलों<sup>27</sup> के 13 मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी की गई थी और तीन अंचलों<sup>28</sup> के पाँच मामलों में कार्रवाई/कार्यवाही शुरू की गई थी। मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल के एक मामले में यह जवाब दिया गया था कि मामला विलोपित किया गया है और सिवान अंचल के एक मामले में केवल संक्षिप्त जवाब "अंतर नहीं" दिया गया था लेकिन कोई सहायक दस्तावेज/साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

शाहाबाद अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZT) ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.06 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 रिटर्न की तालिका-6(डी) में घोषित किया गया है। हालाँकि, करदाता ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न की तालिका-3.1(डी) में रिवर्स चार्ज के तहत शून्य कर देयता स्वीकार की थी। इस प्रकार, करदाता ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.06 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। जवाब में, विभाग ने बताया कि कार्रवाई शुरू की गई थी।

### (III) कर के भुगतान के बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल

पाँच अंचलों के सात करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया।

वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत समकक्ष कर देयता का निर्वहन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा या, दूसरे शब्दों में, रिवर्स चार्ज

<sup>20</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>21</sup> आवक आपूर्ति अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त होती है जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>22</sup> पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>23</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>24</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>25</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>26</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, शाहाबाद और सिवान।

<sup>27</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और समस्तीपुर।

<sup>28</sup> दानापुर, झंझारपुर और शाहाबाद।

मैकेनिज्म के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके किया गया था ताकि यह जाँच जा सके कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर का पूरी तरह से निर्वहन किया गया है या नहीं। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 दाखिल किया गया था, तालिका-4जी<sup>29</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना तालिका-6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-3बी, तालिका-3.1(डी)<sup>30</sup> में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी, तालिका-4ए(2)<sup>31</sup> और 4ए(3)<sup>32</sup> से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच अंचलों<sup>33</sup> में सात करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 1.03 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कर देयता के निर्वहन/भुगतान के उठाया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि, इन सभी मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

बक्सर अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZR) ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ₹ 17.02 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-6(डी) में घोषित किया गया है। हालाँकि, करदाता ने रिवर्स चार्ज के तहत शून्य कर का भुगतान किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-4जी में घोषित किया गया है। इस प्रकार, करदाता ने समानुपातिक कर का भुगतान किए बिना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। इसके जवाब में विभाग ने बताया कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

#### (IV) जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट

**चार अंचलों के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था।**

जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या बही-खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिलान करता है। इस तालिका का कॉलम-12एफ असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधित विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अंचलों<sup>34</sup> के पाँच करदाताओं ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6 करोड़ के असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा की थी, जो लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावा किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में वर्णित है।

<sup>29</sup> आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

<sup>30</sup> आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

<sup>31</sup> सेवाओं का आयात।

<sup>32</sup> आवक आपूर्ति वस्तुओं माल और सेवाओं के आयात के अलावा रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

<sup>33</sup> भभुआ, बक्सर, दानापुर, पटना पश्चिमी और सिवान।

<sup>34</sup> पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष और सहरसा।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि पटना सिटी पश्चिमी और सहरसा अंचल के तीन मामलों में एएसएमटी-10 जारी किया गया था और पटना विशेष अंचल के एक मामले में कार्यवाही प्रगति पर थी। पाटलिपुत्र अंचल के एक मामले में विभाग ने जवाब दिया कि मामला राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल में पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZG) ने जीएसटीआर-9 (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12ई के अनुसार) में ₹ 3.04 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था, जबकि करदाता ने केवल वित्तीय विवरणों (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 डी) के अनुसार ₹ 0.25 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था। इस प्रकार, करदाता ने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में ₹ 2.79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया था, जिसके परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट असमाशोधित था। लेखापरीक्षा पृच्छा के संदर्भ में विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

#### (V) जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में असमाशोधित आवर्त

**13 अंचलों के 26 मामलों में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त को जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित किया गया था।**

जीएसटीआर-9सी की तालिका-5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित सकल आवर्त का वार्षिक आवर्त (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त का मिलान है। इस तालिका के कॉलम-5आर वार्षिक प्रतिवेदन (जीएसटीआर-9) और अपेक्षित समायोजन के बाद के वर्ष के वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त के बीच असमाशोधित लेन-देन को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित समाशोधित विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए आवर्त में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके/जिन मामलों में जीएसटीआर-9 में घोषित आवर्त वित्तीय विवरण से कम है, उनमें अप्रतिवेदन, अपर्याप्त प्रतिवेदन कम प्रतिवेदन, चूक, आपूर्ति की प्रतिवेदन में त्रुटि के कारण चोरी या कर का कम भुगतान होता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों प्रतिवेदित नहीं करने का मामला भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 अंचलों<sup>35</sup> के 26 मामलों में, वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 1,647.19 करोड़ के असमाशोधित आवर्त को जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि 11 अंचलों<sup>36</sup> के 18 मामलों में सूचना (एएसएमटी-10/डीआरसी-01/01ए) जारी किए गए थे चार अंचलों<sup>37</sup> के पाँच मामलों में, करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया और पटना सिटी पश्चिमी अंचल के दो मामलों में, करदाताओं के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह बताया गया था कि ₹ 977.72 करोड़ के असमाशोधित सकल आवर्त में से केवल ₹ 39.28 करोड़ कर योग्य थे,

<sup>35</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पटना मध्य, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर और शाहाबाद।

<sup>36</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, पटना मध्य, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और समस्तीपुर।

<sup>37</sup> शाहाबाद, पटना विशेष, पटना दक्षिणी और पटना उत्तरी।

जिसके लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी।

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन –10XXXXXXXXXX2ZD) के मामले में, जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में घोषित वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 977.72 करोड़ रुपये का असमाशोधित सकल आवर्त देखा गया था, जिसकी सूचना विभाग को दे दी गई थी। विभाग ने (जनवरी 2023) जवाब दिया कि ₹ 977.72 करोड़ के असमाशोधित सकल आवर्त में से ₹ 938.44 करोड़ प्रशासनिक शुल्क, टर्मिनल लाभ, बचत बैंक खातों पर ब्याज पर आय, ऋण/ओवरड्राफ्ट आदि से संबंधित थे, और ₹ 39.28 करोड़ की शेष राशि के लिए, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत कार्यवाही शुरू की जा रही थी। आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

#### (VI) जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में असमाशोधित कर आवर्त

#### 15 अंचलों के 26 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर आवर्त।

जीएसटीआर-9सी की तालिका-7 कर योग्य आवर्त का मिलान है। इस तालिका का कॉलम-7जी वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) और अपेक्षित समायोजन के बाद के वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए कर योग्य आवर्त के बीच असमाशोधित कर योग्य आवर्त को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80 (3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक प्रतिवेदन में प्रतिवेदित कर योग्य आवर्त में पहचाने गए अंतर की सीमा की समीक्षा की जा सके। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 में आवर्त वित्तीय विवरण से कम है, उनमें असमाशोधित राशि गैर-प्रतिवेदन, कम प्रतिवेदन, चूक, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों प्रतिवेदन नहीं करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा नें पाया कि, 15 अंचलों<sup>38</sup> के 26 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में घोषित ₹ 294.73 करोड़ का असमाशोधित कर योग्य आवर्त था, जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 202 से फरवरी 2023) कि कदमकुआँ अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी और 11 अंचलों<sup>39</sup> के 20 मामलों में सूचना (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किया गया था। चार अंचलों<sup>40</sup> के चार मामलों में यह बताया गया कि करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और पटना सिटी पश्चिमी अंचल के एक मामले में करदाता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और नोटिस जारी किया गया था।

<sup>38</sup> औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर, सासाराम, शाहाबाद और सिवान।

<sup>39</sup> औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, कदमकुआँ, मोतिहारी, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी, समस्तीपुर और सिवान।

<sup>40</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी, सासाराम, शाहाबाद और गाँधी मैदान।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना मध्य अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन- 10XXXXXXXXXX1ZS) ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-7जी में ₹ 96.23 करोड़ कहा (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था और आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

**(VII) जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में असमाशोधित कर देयता**

**13 अंचलों के 19 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान।**

वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था ताकि वार्षिक रिटर्न और बही-खातों के बीच भुगतान किए गए कर में पहचाने गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके। प्रपत्र जीएसटीआर-9सी की तालिका-9 में आवर्त को दर-वार अलग करके और वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) के अनुसार किए गए कर के साथ इसकी तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास किया गया है। असमाशोधित राशि संभवतः गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य आवर्त को छूट के रूप में गलत तरीके से चित्रित कर सकती है या इसके विपरीत केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/बिहार माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर/उपकर की गलत उदग्रहण का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है 2017-18 लेनदेन के सापेक्ष अप्रैल से सितंबर 2018 तक किए गए संशोधन (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का सकल) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर घट जाता है। परिणामी ब्याज भुगतान – लघु भुगतान और गलत मदों के तहत भुगतान दोनों- की भी इस संबंध में जाँच करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 अंचलों<sup>41</sup> के 19 मामलों में जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में ₹ 8.90 करोड़ के कर का असमाशोधित भुगतान किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी से फरवरी 2023) कि पूर्णिया अंचल के एक मामले में असमाशोधित कर राशि की वसूली कर ली गई थी, सात अंचलों<sup>42</sup> के 12 मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किया गया था और पटना विशेष अंचल के एक मामले में कार्यवाही चल रही थी। तीन अंचलों<sup>43</sup> के तीन मामलों में यह बताया गया कि करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और सारण अंचल के दो मामलों में डीआरसी-07 आदेश जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

सारण अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZU) ने जीएसटीआर-9सी की तालिका-9आर में घोषित ₹ 0.42 करोड़ (सीजीएसटी-₹ 0.21 करोड़ और एसजीएसटी-₹ 0.21 करोड़) के कर का भुगतान नहीं किया था। लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, करदाता ने 26 जुलाई 2022 को डीआरसी-03 के माध्यम से ₹ 0.42 करोड़ के

<sup>41</sup> औरंगाबाद, भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, जमुई, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण और सिवान।

<sup>42</sup> औरंगाबाद, भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और सिवान।

<sup>43</sup> दानापुर, गाँधी मैदान और मुजफ्फरपुर पश्चिमी।



असमाशोधित कर का भुगतान किया और अंचलों द्वारा ₹ 0.40 करोड़ के ब्याज के भुगतान की माँग जारी की गई।

### (VIII) प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

**नौ अंचलों में 14 करदाताओं ने वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया।**

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सेवा वितरक द्वारा हस्तांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक है, करदाता के रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में स्थानांतरित इनपुट टैक्स क्रेडिट से की जाती है। अपनाई गई पद्धति इस राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका-6जी<sup>44</sup> या जीएसटीआर-3बी की तालिका-4(ए)4<sup>45</sup> की तुलना संबंधित इनपुट सेवा वितरक के जीएसटीआर-6 की तालिका-5ए<sup>46</sup>, तालिका-8ए<sup>47</sup> और तालिका-9ए<sup>48</sup> के योग से करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नौ अंचलों<sup>49</sup> के अधीन 14 करदाताओं ने, वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2.43 करोड़ के लिए अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.10 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (अप्रैल 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि सात अंचलों<sup>50</sup> के 10 मामलों में नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>51</sup> के दो मामलों में मामला आंतरिक लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था और पटना विशेष अंचल का एक मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण अदालत में विचाराधीन था। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह बताया गया कि इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट के कारण था, जिसे करदाता द्वारा ट्रान-1 के माध्यम से दावा किया गया था और मामला हटा दिया गया था। यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ₹ 9.27 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे की तुलना में करदाता द्वारा दाखिल ट्रान-1 और ट्रान-2 रिटर्न में केवल ₹ 5.23 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि ₹ 19.43 लाख (ब्याज और अर्थदण्ड सहित) के लिए फॉर्म डीआरसी-07 में माँग 23 जनवरी 2023 को जारी की गई थी।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचलों के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZS) ने वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 3.79 करोड़ का इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट प्राप्त किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-6(जी) में घोषित किया गया था, लेकिन इनपुट सेवा वितरक द्वारा केवल ₹ 3.18 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर-6 रिटर्न की तालिका (5ए+8ए+9ए) में स्थानांतरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.61 करोड़ के इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का अधिक लाभ उठाया गया। जब इसे इंगित किया गया तब विभाग ने बताया कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।

<sup>44</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त हुआ।

<sup>45</sup> इनपुट सेवा वितरक से आवक आपूर्ति।

<sup>46</sup> कर अवधि के लिए पात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का वितरण।

<sup>47</sup> इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल पुनः प्राप्त और वितरित किया गया।

<sup>48</sup> गलत प्राप्तकर्ता को वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुनर्वितरण।

<sup>49</sup> दानापुर, गाँधी मैदान, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी और पटना विशेष।

<sup>50</sup> दानापुर, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी और पटना दक्षिणी

<sup>51</sup> गाँधी मैदान और पटना विशेष।

### (IX) विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 यह प्रावधित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के अन्दर सरकार को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई हिस्सा अभूगतेय रहता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करें।

2017-18 के दौरान कर प्रेषण में विलम्ब के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, नौ अंचलों के अधीन 13 मामलों<sup>52</sup> में जुलाई 2017 से मार्च 2018 के महीनों से संबंधित जीएसटीआर-3बी रिटर्न 50 से 780 दिनों की विलम्ब से दायर किए गए थे, जिसमें ₹ 22.68 करोड़ की कर देयता शामिल थी। हालाँकि, करदाताओं द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 2.76 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की बकाया ब्याज देयता हुई जैसा कि **परिशिष्ट 11** में बताया गया है।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि पाँच अंचलों के छह मामलों<sup>53</sup> में राशि वसूल की गई, चार अंचलों<sup>54</sup> के चार मामलों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए और शाहाबाद अंचल के दो मामलों में कार्रवाई शुरू की गई। पटना सिटी पूर्वी अंचल के एक मामले में जवाब दिया गया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं कर सका, लेकिन कर की रकम राशि लेजर में क्रेडिट हो गई। यह जवाब स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि केवल क्रेडिट की उपलब्धता को कर देयता के भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि इसे कर देयता के निर्वहन के लिए डेबिट नहीं किया जाता है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना दक्षिणी अंचल के अधीन एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZB) ने मार्च 2018 महीने से संबंधित जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया था, जिसमें मार्च 2020 में ₹ 1.36 करोड़ की कर देनदारी शामिल थी, यानी 691 दिनों की देरी से और बकाया करों का भुगतान किया। हालाँकि, करदाता द्वारा कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 44.80 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि डीआरसी-01 जारी कर दिया गया है।

### (X) अभुक्त कर देयता

**वर्ष 2017-18 के लिए 11 अंचलों के 14 मामलों में, ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर।**

जीएसटीआर-1 वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का मासिक ब्यौरा दर्शाता है। इस विवरण का मूल्यांकन करदाता द्वारा भी किया जाता है और संबंधित कॉलम में वार्षिक

<sup>52</sup> बेगूसराय, गाँधी मैदान, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, सारण, सासाराम, शाहाबाद और सिवान।

<sup>53</sup> बेगूसराय, गाँधी मैदान, हाजीपुर, सासाराम और सिवान।

<sup>54</sup> हाजीपुर, पटना दक्षिणी, सारण और सासाराम।



रिटर्न जीएसटीआर-9 में उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

अभुक्त कर देयता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से संबंधित आँकड़े निकाले गए और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर से की गई। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। एल्गोरिथम के लिए जीएसटीआर-1 की तालिका-4 से 11 और जीएसटीआर-9 की तालिका-4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 में घोषित कर से की गई ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर-3बी के मामले में, तालिका-3.1(ए)<sup>55</sup> और तालिका-3.1(बी)<sup>56</sup> को ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>57</sup> के 14 मामलों में ₹ 205.31 करोड़ की कर देयता राशि की कर अदा की गई थी एवं केवल ₹ 103.21 करोड़ के कर का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 101.77 करोड़ की कर देयता का अंतर हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि पटना मध्य अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी, आठ अंचलों<sup>58</sup> के आठ मामलों में करदाताओं को नोटिस (एएसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>59</sup> के तीन मामलों में, करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और दो अंचलों<sup>60</sup> के दो मामलों में, करदाताओं को डीआरसी-07 प्रपत्र में आदेश जारी किए गए थे।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पूर्णिया अंचल के अधीन आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZQ) ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 में ₹ 0.41 करोड़ और जीएसटीआर-9 में ₹ 39.48 करोड़ की कर देनदारी दिखाई थी। हालाँकि, करदाता ने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 39.48 करोड़ की कर देयता (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता) हो गई। जवाब में, विभाग ने (जनवरी 2023) बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

<sup>55</sup> बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, निल रेटेड और छूट के अलावा)।

<sup>56</sup> बाहरी कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड)।

<sup>57</sup> भागलपुर, हाजीपुर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णिया, सासाराम और शाहाबाद।

<sup>58</sup> भागलपुर, हाजीपुर, लखीसराय, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना विशेष, पटना दक्षिणी और शाहाबाद।

<sup>59</sup> मुजफ्फरपुर पश्चिमी और सासाराम।

<sup>60</sup> पाटलिपुत्र और पूर्णिया।

**(X) ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है**

**11 अंचलों के, 12 करदाताओं ने जीएसटीआर-1 दाखिल किया था एवं जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 सपटित बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61(5) में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। डेटा स्तर पर लेखापरीक्षा में उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया, जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, परन्तु, जीएसटीआर-1 दाखिल किया था या जिनका जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर-3बी रिटर्न एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देनदारी की भरपाई की जाती है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करने से संकेत मिलता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान कारोबार किया था, लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया था। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और उन मामलों को निकाला गया जहाँ जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 11 अंचलों<sup>61</sup> के अधीन 12 करदाताओं ने जीएसटीआर -1 दाखिल किए बिना वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता घोषित की थी, लेकिन उन्होंने जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.91 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं हुआ। यह भी देखा गया कि इन करदाताओं के पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे जैसा कि परिशिष्ट 2.13 में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने (मार्च 2022) पर, विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि सात अंचलों<sup>62</sup> के सात मामलों में नोटिस/एएसएमटी-10/डीआरसी-01, जारी किया गया था, पटना उत्तरी और सारण अंचलों के दो मामलों में डीआरसी-07 में माँग जारी की गई और गया अंचल के एक मामले में करदाता का पंजीकरण रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने कैश/क्रेडिट लेजर के अनुसार कोई कर जमा नहीं किया गया था। पटना विशेष अंचल के एक मामले में, यह जवाब दिया गया था कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी। बिहारशरीफ अंचल के एक मामले में विभाग ने बताया कि अंचलों में करदाता से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो स्वीकार्य नहीं है।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZZ) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 52.81 लाख रुपये की कर देनदारी स्वीकार की थी, लेकिन करदाता ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था और कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 52.81 लाख की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया। जवाब में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रक्रिया में थी।

**ख) ऐसे मामले जहाँ विभाग का जवाब लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है**

184 गैर-अनुपालन मामलों में से, विभाग ने 11 मामलों में ₹ 8.36 करोड़ की राशि के लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार नहीं किया था जैसा कि नीचे तालिका 8 में वर्णित है।

<sup>61</sup> औरंगाबाद, बिहारशरीफ, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना विशेष, सारण और सिवान।

<sup>62</sup> औरंगाबाद, दानापुर, गाँधी मैदान, हाजीपुर, पटना सिटी पश्चिमी और सिवान।

**तालिका 8**  
**ऐसे मामले जहाँ विभाग की प्रतिक्रिया का खंडन किया गया**  
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	अंचल	आयाम	बेमेल राशि
1.	10XXXXXXXXXX1ZJ	पाटलिपुत्र	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.84
2.	10XXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	4.03
3.	10XXXXXXXXXX1ZV	सासाराम	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.73
4.	10XXXXXXXXXX1Z4	पटना विशेष	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	1.13
5.	10XXXXXXXXXX1ZM	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	बेमेल इनपुट टैक्स क्रेडिट	0.86
6.	10XXXXXXXXXX1ZK	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	0.20
7.	10XXXXXXXXXX1Z2	सिवान	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ	0.23
8.	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना सिटी पूर्वी	ब्याज का भुगतान न होना	0.20
9.	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना विशेष	इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का गलत लाभ	0.09
10.	10XXXXXXXXXX1ZE	गया	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया	0.04
11.	10XXXXXXXXXX1ZR	बिहारशरीफ	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया	0.00
<b>कुल</b>				<b>8.35</b>

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना सिटी पूर्वी अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z6) के मामले में जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में विलम्ब के कारण ₹ 0.20 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं होने की सूचना विभाग को दी गई थी। विभाग ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सका लेकिन कर राशि कैश लेजर में जमा कर दी गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देयता का निर्वहन केवल तभी वैध माना जाता है जब कैश लेजर में संबंधित डेबिट होता है। चूंकि कर देनदारी तय तारीख तक समायोजित नहीं की गई थी, इसलिए ब्याज वसूलने की जरूरत है।

#### ग) करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ

जहाँ विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था वहाँ डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 13 प्रतिशत (361 मामलों में से 48) और 27 प्रतिशत (177 मामलों में से 48) था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनपुट सेवा वितरक, कारोबार और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर-9सी में प्रदान किया गया) से संबंधित अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ परिशिष्ट 2.14 में वर्णित हैं।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पटना विशेष अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX2ZN) के जीएसटीआर-9सी की तालिका-5आर में ₹ 4,409.38 करोड़ के असमंजित राशि की पहचान की गई और विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने बताया कि विचलन एक टंकण त्रुटि के कारण हुआ था। करदाता ने गलती से जीएसटीआर-9सी की तालिका-5डी में वास्तविक ₹ 4,899.31 करोड़ के बजाय ₹ 489.93 करोड़ की छूट वाली आपूर्ति का संकेत दिया था।

सिस्टम ने ऐसी डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के लिए अनुमति दी, जिन्हें उचित सत्यापन नियंत्रण के साथ टाला जा सकता था।

**घ) लेखापरीक्षा पृच्छा जारी करने से पहले की गई कार्रवाई**

जैसा कि ऊपर तालिका 6 में सारांशित है, विभाग ने पहले ही 29 मामलों में कार्रवाई की थी, जो प्राप्त 361 प्रतिक्रियाओं का आठ प्रतिशत था। विचलनों/विसंगतियों को सक्रिय रूप से संबोधित करने वाले शीर्ष पाँच अंचलों को नीचे तालिका 9 में इंगित किया गया है:

तालिका 9

**लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई**

अंचल	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा की कुल संख्या	प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई (मामलों की संख्या)	लेखापरीक्षा पृच्छा से पहले की गई कार्रवाई का प्रतिशत
सासाराम	4	13	13	31
पटना मध्य	3	30	16	10
नवादा	3	4	4	75
भभुआ	2	18	18	11
भागलपुर	2	11	8	18
<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>145</b>

**अनुशंसा 5: विभाग को माल एवं सेवा कर परिषद को इस तरह की डेटा प्रविष्टि त्रुटि की घटना को कम करने के लिए आवश्यक सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट का प्रस्ताव देना चाहिए।**

**2.3.7.4 माल एवं सेवा कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा**

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। विभाग की भूमिका निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून के अनुपालन और राजस्व के संग्रह को सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल पैमाने पर शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन स्टेट डेटा विश्लेषण के माध्यम से माल एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक हिस्से के रूप में माल एवं सेवा कर रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस हिस्से के लिए 100 करदाताओं का जोखिम आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई पद्धति शुरू में जीएसटीआर-9सी और बैक-एंड व्यवस्था में उपलब्ध अन्य अभिलेख के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दायर माल एवं सेवा कर रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करना था ताकि संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और रेड फ्लैग की पहचान की जा सके। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, करदाताओं के तदनुसारी अभिलेखों जैसे वित्तीय बही-खातों, चालानों आदि की माँग कर के अंचलों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान की जा सके और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से अंततः दाखिल रिटर्न की सत्यता, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन पर असर पड़ता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: (I) रिटर्न, (II) इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग और (III) कर देयता का निर्वहन। विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे तालिका 10 में दिया गया है।

**तालिका 10**  
**विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश**

क्र० सं०	मापदंड	विचलन की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)
1	करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	22	2.62	0.02
2	करदाताओं द्वारा उपयोग में लाये इनपुट टैक्स क्रेडिट से आपूर्तिकर्ता के विवरण के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना	44	60.58	0.25
3	वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ)	4	11.04	0
4	वार्षिक रिटर्न में घोषित की तुलना में जीएसटीआर-3बी में अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेमेल होना (जीएसटीआर-9 की तालिका-6जे)	8	0.54	0
5	कर का कम/नहीं भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा उपयोग में लाये गए और रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति	6	2.12	0
6	जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति	8	0.90	0
7	कर का कम भुगतान	19	7.22	0.02
<b>कुल</b>		<b>111</b>	<b>85.02</b>	<b>0.29</b>

**क) क्षेत्र सीमाएं (अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण)**

बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेख की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता बेमेल से संबंधित जोखिमों की पहचान की। इनपुट टैक्स क्रेडिट आयाम पर जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 से और जीएसटीआर-9 की तालिका-12 और 14 में की गई घोषणाओं से की गई। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका-5, तालिका-7 और तालिका-9 में किए घोषणाओं द्वारा की गई थी। लेखापरीक्षा ने इनपुट टैक्स क्रेडिट और कर देयता के बेमेल होने के कारणों की जाँच करने के लिए संबंधित अंचलों से करदाताओं के बारीक अभिलेखों जैसे पूरक वित्तीय बहीखाता, चालान, समझौते की प्रतियां आदि की माँग की। तथापि, विभाग ने 79 मामलों में तदनुरूपी का प्रस्तुतिकरण नहीं किया। अभिलेखों को अंचल-वार आंशिक प्रस्तुतिकरण का ब्योरा **परिशिष्ट 2.15** में वर्णित है और अभिलेखों के आंशिक प्रस्तुतिकरण के पाँच उच्च जोखिम वाले मामले नीचे **तालिका 11** में दिए गए हैं।

**तालिका 11**  
**अभिलेख के आंशिक प्रस्तुतिकरण के उच्च जोखिम वाले मामले**

(₹ करोड़ में)

जीएसटीआईएन	अंचल	अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण नहीं	डेस्क समीक्षा में पहचाने गए मुद्दों की जाँच नहीं की गई	बेमेल राशि
10XXXXXXXXXX1ZJ	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	212.86
10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	55.63
10XXXXXXXXXX1ZQ	पटना उत्तरी	बिक्री बीजक और लेनदारों/व्यापार देय के साथ गैर-माल एवं सेवा कर आपूर्ति का बहीखाता	गैर-माल एवं सेवा कर आपूर्ति उचित था और यदि बीजक जारी करने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर किया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन विपरीत हो जाता है।	15.39

जीएसटीआईएन	अंचल	अभिलेखों का प्रस्तुतिकरण नहीं	डेस्क समीक्षा में पहचाने गए मुद्दों की जाँच नहीं की गई	बेमेल राशि
10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	30.49
10XXXXXXXXXX4ZJ	पटना विशेष	लेनदारों/व्यापार देय का बहीखाता	यदि बीजक जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर आपूर्ति के मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिवर्सल।	11.45

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, सात अंचलों<sup>63</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि जहाँ तक भौतिक चालान, क्रेडिट/डेबिट नोट और अन्य बही-खातों का संबंध है, माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत करदाताओं के लिए किसी भी कार्यवाही के अभाव में क्षेत्राधिकार कार्यालय में स्वतः एक भौतिक प्रति प्रस्तुत करना नहीं कहा गया है। 11 अंचलों<sup>64</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी, जबकि पाँच अंचलों<sup>65</sup> के सक्षम अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख प्रदान किए गए हैं। पाँच अंचलों<sup>66</sup> के उचित अधिकारियों ने कहा कि करदाताओं से अभिलेख मांगे जाएंगे और लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गया अंचल के सक्षम अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया।

विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि उपरोक्त अभिलेख विभाग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं थे और करदाता, अधिनियम की धारा 65 के तहत लेखापरीक्षा प्रारंभ होने पर इन अभिलेखों को प्रस्तुत करते हैं।

## I. रिटर्न

100 करदाताओं द्वारा दायर रिटर्न के नमूनों की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था, जिसे नीचे लाया गया है:

### अ) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं करना

**16 अंचलों के 22 मामलों (नौ जाँचित मामलों सहित) में, करदाताओं ने एक से 1,060 दिनों की देरी से अपना रिटर्न दाखिल किया, लेकिन ब्याज भुगतान के ₹ 2.62 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 50 (1) के अनुसार, एक करदाता को निर्धारित अवधि के अन्दर कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहने पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। 2017-18 के दौरान कर प्रेषण में देरी के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान कर जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का निर्धारण करने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया था।

<sup>63</sup> बक्सर, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, शाहाबाद और सिवान।

<sup>64</sup> औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, पटना सिटी पूर्वी, पटना पश्चिमी, रक्सौल, सहरसा, सारण, सासाराम, सीतामढ़ी और तेघरा।

<sup>65</sup> फारबिसगंज, कदमकुआँ, नवादा, पटना मध्य और सुपौल।

<sup>66</sup> भभुआ, दानापुर, गाँधी मैदान, मुजफ्फरपुर पश्चिमी और पटना दक्षिणी।

लेखापरीक्षा ने 16 अंचलों<sup>67</sup> के 22 मामलों (नौ जाँचित मामलों सहित) में, पाया कि, लेखापरीक्षित 100 मामलों के 22 प्रतिशत सन्निहित करदाताओं ने एक से 1,060 दिनों की देरी से अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में वर्णित है।

शीर्ष पाँच मामले नीचे **तालिका 12** में दिया गया है।

**तालिका 12**  
**ब्याज का भुगतान न करने के शीर्ष पाँच मामले**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX2ZI	बक्सर	0.96
2.	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	0.64
3.	10XXXXXXXXXX1ZV	औरंगाबाद	0.36
4.	10XXXXXXXXXX1ZU	पटना विशेष	0.24
5.	10XXXXXXXXXX1Z3	मुजफ्फरपुर पूर्वी	0.08

इसे इंगित किये जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि सुपौल अंचल के एक मामले में राशि वसूल की गई थी, सात अंचल<sup>68</sup> के 10 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए थे, दो अंचलों<sup>69</sup> के दो मामलों में कार्रवाई किया गया, तीन अंचलों<sup>70</sup> के तीन मामलों में करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और औरंगाबाद अंचल के एक मामले में सुनवाई चल रही थी। हालाँकि, जिस धारा के तहत सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी उल्लिखित नहीं था। पाँच अंचलों<sup>71</sup> के पाँच मामलों में जवाब की प्रतीक्षित था (जून 2023)।

दो उदाहरणात्मक मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- पाटलिपुत्र अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z7) पर वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 2.70 करोड़ की कर देयता थी, जबकि उसने केवल ₹ 1.29 करोड़ के कर का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ। यह देखा गया कि करदाता ने नवंबर 2020 में डीआरसी-03 के तहत ₹ 1.41 करोड़ के बकाये कर का भुगतान किया था, यानी 30 महीने की देरी से। इस प्रकार, करदाता कर के भुगतान में देरी के लिए ₹ 0.64 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जब इसे इंगित किया गया तो विभाग ने बताया कि डीआरसी-01 जारी किया गया था।
- औरंगाबाद अंचल के तहत आने वाले एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZV) ने मार्च 2019 में यानी 344 दिनों की विलम्ब से मार्च 2018 महीने के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न को दाखिल किया था कि, ₹ 2.10 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.36 करोड़ की ब्याज देयता का निर्वहन नहीं किया गया। जब इसे इंगित किया गया, तो विभाग ने बताया कि मामला प्रक्रियाधीन है।

<sup>67</sup> औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, दानापुर, फारबिसगंज, गया, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, शाहाबाद, सिवान, सीतामढ़ी और सुपौल।

<sup>68</sup> औरंगाबाद, बक्सर, फारबिसगंज, गया, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र और सिवान।

<sup>69</sup> पाटलिपुत्र और शाहाबाद।

<sup>70</sup> दानापुर, पटना उत्तरी और पटना विशेष।

<sup>71</sup> भभुआ, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना उत्तरी और सीतामढ़ी।



## II. इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपयोगिता

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है, किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया माल और सेवा कर जो व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तों को निर्धारित करती है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर क्रेडिट का उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्र शासीत माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्र शासीत माल एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। बिहार माल एवं सेवा कर नियमों के नियम 36 से 45 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और उसे प्रत्यवितित करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

### अ) करदाताओं द्वारा उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपूर्तिकर्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट से बेमेल होना

**23 अंचलों के 44 विभिन्न करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ बेमेल।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 42 और बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017, के नियम 60 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, रिवर्सल और पुनः प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 44 को नियमों के नियम 80 के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है। जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो माल एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। जब कोई आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करता है तो उसकी जानकारी जीएसटीआर-2ए में दर्ज हो जाती है। यह विक्रेता के जीएसटीआर-1 से उन वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी लेता है जो किसी दिए गए महीने में खरीदी गई हैं। जीएसटीआर-2ए के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न या वार्षिक जीएसटीआर-9 रिटर्न के माध्यम से करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से मेल खानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया कि 23 अंचलों<sup>72</sup> के 44 करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-3बी/9 के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 310.38 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया, लेकिन जीएसटीआर-2ए में केवल ₹ 249.60 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था। इसलिए, विभिन्न पंजीकृत करदाताओं से प्राप्त इनपुट आपूर्ति पर ₹ 60.58 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंतर था जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में वर्णित है। शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 13 में दी गई हैं।

#### तालिका 13

#### इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित लाभ के शीर्ष पाँच मामले

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX1ZS	पटना मध्य	15.59
2.	10XXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	10.03
3.	10XXXXXXXXXX1ZM	पाटलिपुत्र	9.95
4.	10XXXXXXXXXX1ZT	पाटलिपुत्र	3.82
5.	10XXXXXXXXXX1ZR	पटना विशेष	3.01

<sup>72</sup> औरंगाबाद, बेगूसराय, भभुआ, दानापुर, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, गया, गोपालगंज, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, समस्तीपुर, सारण, सासाराम, शाहाबाद और सीतामढ़ी।



इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से नवंबर 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि 11 अंचलों<sup>73</sup> के 19 मामलों में नोटिस/आदेश जारी किए गए, चार अंचलों<sup>74</sup> के 13 मामलों में करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया और पाटलिपुत्र अंचल के एक मामले में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन किया गया। आठ अंचलों<sup>75</sup> के 11 मामलों में जवाब (मार्च 2023) प्रतिक्षित था।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन- 10XXXXXXXXXX1ZM) ने ₹ 21.36 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया था (जीएसटीआर-3बी की तालिका-6बी(5) से जीएसटीआर-9 की तालिका-7(एच) में रिवर्सल को छोड़कर, परन्तु बाद के वर्ष 2018-19 में उपयोगित इनपुट टैक्स क्रेडिट को जोड़कर मौजूद था (जीएसटीआर-9 की तालिका-8सी) जबकि जीएसटी-2ए के अनुसार कुल ₹ 11.41 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 9.95 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में अंतर था। जवाब में, विभाग ने कहा कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

### ब) वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के बीच असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट

**तीन अंचलों के चार मामलों में वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था।**

जीएसटीआर-9सी की तालिका-12 में वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या बही-खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया गया है। इस तालिका का कॉलम-12एफ असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। वर्ष 2017-18 के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-9सी में बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के तहत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेमेल की पहचान करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, तीन अंचलों<sup>76</sup> के चार मामलों में वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 11.04 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट था। यह असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 39.30 करोड़ के वार्षिक रिटर्न के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट और ₹ 28.26 करोड़ के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या बही-खातों के अनुसार प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का अंतर था जो कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने (जून 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि पाटलिपुत्र अंचल के दो मामलों में डीआरसी-01ए/डीआरसी-7 जारी किए गए थे और दो अंचलों के दो मामलों में<sup>77</sup> करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

<sup>73</sup> औरंगाबाद, बेगूसराय, फारबिसगंज, गया, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी, सारण, समस्तीपुर और सासाराम।

<sup>74</sup> दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पटना विशेष और शाहाबाद।

<sup>75</sup> भभुआ, गांधी मैदान, गोपालगंज, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी और सीतामढ़ी।

<sup>76</sup> दानापुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी और पाटलिपुत्र।

<sup>77</sup> दानापुर और मुजफ्फरपुर पश्चिमी।

एक उदाहरणात्मक मामला का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZM) ने जीएसटीआर-9 में ₹ 21.36 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12ई के अनुसार) जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार करदाता ने ₹ 14.40 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था (जीएसटीआर-9सी की तालिका-12डी के अनुसार)। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-9सी की तालिका-12एफ में ₹ 6.96 करोड़ का असमाशोधित इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ। जवाब में, विभाग ने बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

**स) वार्षिक रिटर्न में घोषित जीएसटीआर-3बी से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर**

**आठ अंचलों के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर-9 रिटर्न के तालिका-6जे में प्रतिबिंबित है।**

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 80 (1) के अनुसार इनपुट सेवा वितरक के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, प्रपत्र जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा। जीएसटीआर-3बी के जरिए दावा किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6ए, जीएसटीआर-3बी में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुल योग है जो स्वतः परिलक्षित और गैर-संपादन योग्य है। तालिका-6बी से 6एच के माध्यम से करदाता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का विभाजन प्रदान करता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6ए के साथ इन तालिकाओं की तुलना से पता चलता है कि अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाए जाने की संभावना का पता लगता है। जीएसटीआर-9 की तालिका-6जे में जीएसटीआर-3बी के माध्यम से उपयोगित इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटीआर-9 की तालिका-6आई में घोषित इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल उपयोग के अंतर को दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ अंचलों<sup>78</sup> के आठ मामलों (बिना जाँच किए गए) में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में ₹ 0.54 करोड़ का अंतर था जैसा कि जीएसटीआर-9 विवरणी की तालिका-6जे में दर्शाया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट 2.19** में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे **तालिका 14** में दी गई हैं।

**तालिका 14**

**इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ उठाने के शीर्ष पाँच मामले**

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX1ZN	दानापुर	0.20
2.	10XXXXXXXXXX1ZP	गाँधी मैदान	0.11
3.	10XXXXXXXXXX1ZN	दरभंगा	0.10
4.	10XXXXXXXXXX2ZG	तेघरा	0.08
5.	10XXXXXXXXXX1Z6	पटना मध्य	0.03

इसे इंगित किये जाने (जून 2022 से अगस्त 2022) पर विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि तीन अंचलों<sup>79</sup> के तीन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे और दानापुर अंचलों के एक मामले को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गया अंचल के एक मामले में, यह बताया गया था कि अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

<sup>78</sup> भभुआ, दानापुर, दरभंगा, गाँधी मैदान, गया, पाटलिपुत्र, पटना मध्य और तेघरा।

<sup>79</sup> दरभंगा, पाटलिपुत्र और तेघरा।

नहीं उठाया गया था, लेकिन आदेश की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। तीन अंचलों<sup>80</sup> के तीन मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

दानापुर अंचल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1ZM) ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत ₹ 84.95 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग किया था, जैसा कि जीएसटीआर-9 की तालिका-6ए में घोषित किया गया है, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका-6आई में केवल ₹ 84.75 करोड़ का विभाजन प्रदान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर-3बी और वार्षिक रिटर्न में घोषित ₹ 0.20 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंतर हो गया। जवाब में, विभाग ने बताया कि करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और आपत्ति को लेखापरीक्षा में शामिल किया जाएगा।

**द) कर का नहीं/अल्प भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स चार्ज के तहत किए गए भुगतान के बीच विसंगति**

**2017-18 की अवधि के लिए पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस पर कर का भुगतान ऐसे वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे, यदि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पटना उत्तरी और पटना विशेष अंचलों के तीन करदाताओं ने 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 2.01 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, लेकिन रिवर्स चार्ज के तहत केवल ₹ 0.04 करोड़ के कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने में ₹ 1.98 करोड़ की विसंगति उत्पन्न हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.20(क)** में वर्णित है। इसके अलावा, हाजीपुर, जहानाबाद और सासाराम अंचलों के तीन करदाताओं ने माल परिवहन सेवा के लिए 2017-18 के दौरान ₹ 2.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसे रिवर्स चार्ज के तहत अधिसूचित किया गया था, लेकिन करदाताओं ने रिवर्स चार्ज के तहत ₹ 0.14 करोड़ का कर नहीं चुकाया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.20(ख)** में वर्णित है। यह भी पाया गया कि इन सभी मामलों में धारा 61 के तहत जाँच की गई थी और एएसएमटी-10 में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उपरोक्त विसंगति को पाँच मामलों में इंगित नहीं किया गया था और एक मामले में, इसे इंगित किया गया था, लेकिन आगे इसका पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.14 करोड़ का कर का भुगतान नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि सासाराम अंचल के एक मामले में करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था और जहानाबाद अंचल के एक मामले में ब्याज के साथ कर राशि वसूल की गई थी। तीन अंचलों<sup>81</sup> के चार मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (जून 2023)।

<sup>80</sup> भभुआ, गाँधी मैदान और पटना मध्य।

<sup>81</sup> हाजीपुर, पटना उत्तरी और पटना विशेष।

**III. कर देयता का निर्वहन****अ) जीएसटीआर-1 की तुलना में जीएसटीआर-9/3बी में कर देयता की कम स्वीकृति**

**करदाताओं ने ₹ 0.90 करोड़ के कम कर देयता स्वीकार किया।**

जीएसटीआर-1 में वस्तुओं या सेवाओं की बाह्य आपूर्ति का मासिक ब्यौरा दर्शाया गया है। इस विवरण का मूल्यांकन करदाता द्वारा भी किया जाता है और संबंधित कॉलम में वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3 बी में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2017-18 के लिए आठ अंचलों<sup>82</sup> के आठ करदाताओं (तीन जाँचित मामलों सहित) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 26.62 करोड़ की कर देयता की घोषणा की थी, जबकि जीएसटीआर-9/3बी के अनुसार, करदाताओं ने केवल ₹ 25.72 करोड़ की कर देयता स्वीकार किया था। इस प्रकार, करदाताओं ने ₹ 0.90 करोड़ की लघु कर देयता स्वीकार किया था जैसा कि **परिशिष्ट 2.21** में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे **तालिका 15** में दी गई हैं।

**तालिका 15****कर देयता के कम स्वीकारोक्ति के शीर्ष पाँच मामले**

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX1Z7	पाटलिपुत्र	0.34
2.	10XXXXXXXXXX1ZR	फारबिसगंज	0.30
3.	10XXXXXXXXXX1ZP	गाँधी मैदान	0.08
4.	10XXXXXXXXXX1ZC	पटना उत्तरी	0.07
5.	10XXXXXXXXXX1ZG	कदमकुआँ	0.05

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया कि (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि चार अंचलों<sup>83</sup> के चार मामलों में करदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे। चार अंचलों<sup>84</sup> के चार मामलों में जवाब प्रतीक्षित था (मार्च 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

पाटलिपुत्र अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन-10XXXXXXXXXX1Z7) ने वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 में केन्द्रीय माल एवं सेवा कर/राज्य माल एवं सेवा कर/एकीकृत माल एवं सेवा कर के तहत ₹ 86.31 लाख की कर देयता स्वीकार किया था, जबकि उसने केवल जीएसटीआर-9 में केवल ₹ 52.27 लाख की कर देयता स्वीकार की थी। इस प्रकार, करदाता ने जीएसटीआर-1 में दर्शाई गई कर देयता की तुलना में वार्षिक रिटर्न में ₹ 34.04 लाख की क्रम कर देयता को स्वीकार किया है। जवाब में, विभाग ने बताया कि डीआरसी-07 जारी किया गया था।

<sup>82</sup> फारबिसगंज, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, पाटलिपुत्र और सासाराम।

<sup>83</sup> फारबिसगंज, पटना उत्तरी, पाटलिपुत्र और सासाराम।

<sup>84</sup> गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पूर्वी और पटना मध्य।

**ब) कर का कम भुगतान**

**16 अंचलों के 19 करदाताओं (तीन जाँचित/मूल्यांकित मामलों सहित) ₹ 7.22 करोड़ के कर का कम भुगतान।**

वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में विभिन्न मदों (केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, राज्य माल एवं सेवा कर, एकीकृत माल एवं सेवा कर और उपकर) के तहत वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है। जीएसटीआर-9सी, जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बीच एक समाशोधन विवरण है। जीएसटीआर-9/9सी में घोषित कर देयता की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 में घोषित कर भुगतान से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, 16 अंचलों<sup>85</sup> के 19 करदाताओं (तीन जाँचित/मूल्यांकित मामलों सहित) ने जीएसटीआर-9/9सी में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 72.54 करोड़ की कर देयता स्वीकार किया था, जबकि जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 के अनुसार कर भुगतान राशि केवल ₹ 65.33 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.22 करोड़ के कम कर भुगतान हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में वर्णित है।

शीर्ष पाँच अनियमितताएं नीचे तालिका 16 में दी गई हैं।

**तालिका 16**  
**कर के कम भुगतान के शीर्ष पाँच मामले**

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	जीएसटीआईएन	अंचल	शामिल राशि
1.	10XXXXXXXXXX2ZE	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	1.26
2.	10XXXXXXXXXX1ZK	सिवान	1.05
3.	10XXXXXXXXXX2Z7	कदमकुआँ	0.84
4.	10XXXXXXXXXX1ZK	शाहाबाद	0.70
5.	10XXXXXXXXXX1ZG	शाहाबाद	0.68

इसे इंगित किए जाने (मई 2022 से अगस्त 2022) पर, विभाग ने बताया (जनवरी 2023 से फरवरी 2023) कि नौ अंचलों<sup>86</sup> के नौ मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, शाहाबाद अंचल के दो मामलों में करवाई शुरू की गई और मुजफ्फरपुर पश्चिमी के एक मामले में, करदाता को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। गया अंचल के एक मामले में यह बताया गया कि कर का कोई कम भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन आदेश की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। पाँच अंचलों<sup>87</sup> के छह मामलों में जवाब प्रतिक्रिया था (जून 2023)।

एक उदाहरणात्मक मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

यह पाया गया कि मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन -10XXXXXXXXXX2ZE) ने जीएसटीआर-1 में ₹ 32.72 करोड़ की कर देयता घोषित की थी, हालाँकि, जीएसटीआर-9 की तालिका-9 और 14 के अनुसार, उसने केवल ₹ 31.46 करोड़ की कर देयता का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की कर राशि का कम भुगतान हुआ। जवाब में, विभाग ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा में मामले की जाँच की जा रही है।

<sup>85</sup> भभुआ, बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, गोपालगंज, कदमकुआँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिणी, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, शाहाबाद और सिवान।

<sup>86</sup> बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, मोतिहारी, पाटलिपुत्र, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम और सिवान

<sup>87</sup> भभुआ, गोपालगंज, कदमकुआँ, पटना मध्य और पटना दक्षिणी।

**स) आपूर्ति का अपवर्जन**

सासाराम और शाहाबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ के 'व्यावसायिक संपत्तियों के हस्तांतरण और स्कैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 वस्तुओं और सेवाओं या दोनों का सम्मिलित करने के लिए आपूर्ति को परिभाषित करती है जैसे विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनियम, विनियम, अनुज्ञप्ति, किराये, पट्टे या व्ययन जो व्यापार को आगे बढ़ाने में व्यक्ति द्वारा विचारणीय होता है। इसमें सेवाओं के आयात चाहे वह कारोबारी के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं को भी शामिल किया जाता है। यह एक समावेशी परिभाषा है, मुख्य तत्व (1) आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति को विचार के लिए किया जाना चाहिए, (3) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने में की जानी चाहिए, (4) आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति एक कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, और (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करती है जो बिना किसी विचार के भी की जाती हैं, उन्हें आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अनुसूची II, कुछ गतिविधियों या लेनदेन को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मानने को निर्दिष्ट करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सासाराम और शाहाबाद अंचलों के दो करदाताओं ने 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 2.58 करोड़ में 'व्यावसायिक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण और स्कैप बिक्री' की कर योग्य आपूर्ति की थी, लेकिन उस पर लागू कर का भुगतान नहीं किया था जैसा कि नीचे तालिका 17 में दिया गया है।

**तालिका 17**  
**कर योग्य आपूर्ति पर कर का भुगतान न करना**

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	अंचल का नाम	जीएसटीआईएन	आपूर्ति का मूल्य
1.	सासाराम	10XXXXXXXXXX1ZO	0.96
2.	शाहाबाद	10XXXXXXXXXX1ZK	1.62
<b>कुल</b>			<b>2.58</b>

आगे, यह पाया गया कि, सासाराम अंचल के एक मामले में, धारा 61 के तहत जाँच की गई थी और सूचना (एएसएमटी-10) जारी किया गया था, लेकिन सूचना में उपरोक्त विसंगति को इंगित नहीं किया गया था।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (जून 2023)।

**अनुशंसा 6: विभाग समय सीमा समाप्त होने से पहले इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।**

**2.3.8 अन्य निरीक्षण कार्य**

अंचलों (विभागीय क्षेत्र संरचनाओं) की भूमिका रिटर्न दाखिल करने, कर देयता और अन्य अनुपालन दायित्वों का निर्वहन करने के संबंध में करदाताओं के अनुपालन पर निगरानी प्रदान करना है। रिटर्न दाखिल करने, देर से/दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई और संवीक्षा से संबंधित निरीक्षण कार्यों पर इस रिपोर्ट के पिछले खंडों में चर्चा की गई है। यह खंड पंजीकरण रद्द करने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है।



बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 और बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 20 में कारोबार बंद होने, पंजीकरण के लिए सीमा से नीचे कारोबार करने, कारोबार हस्तांतरण/विलय/समामेलन, पेन में बदलाव, निर्धारित समय अवधि के अंदर कारोबार शुरू नहीं करने और मालिक की मृत्यु जैसी कुछ स्थितियों में करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करने की अनुमति दी गई है। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को माल एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल पर आरईजी-16 में "रद्दीकरण की गारंटी देने वाली घटना की घटना" के 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा।

अधिनियम की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने, कंपोजिशन करदाताओं को लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाताओं को छह महीने की निरंतर अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण की तारीख से छह महीने के अंदर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छुपाने के माध्यम से प्राप्त पंजीकरण के आधार पर व्यवसाय शुरू नहीं करने की अनुमति देता है।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 45 में (अ) इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ब) कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (स) धारा 51 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति – टीडीएस संग्रह या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति – टीडीएस कटौती के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दाखिल करना होगा, रद्द करने की प्रभावी तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख के तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का निर्वहन करता है। जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने की स्थिति में कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए अपनाई जाती है।

लेखापरीक्षा ने रद्दीकरण क्रियाकलाप का मूल्यांकन करने के लिए नौ अंचलों के एक नमूने का चयन किया और पाई गई कमियों को नीचे बताया गया है:

### 2.3.8.1 अंचलों में पंजीकरण रद्द करने के संबंध में सूचना की अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धता

पंजीकरण रद्द करने के संबंध में जानकारी अर्थात्, रद्द करने के लिए करदाताओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या, कर अधिकारियों द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू किए गए रद्दीकरण की संख्या आदि, नौ चयनित अंचलों से मांगी गई थी। नौ अंचलों में से पाँच अंचलों<sup>88</sup> या तो कोई सूचना नहीं दी या दोषपूर्ण करदाताओं का पंजीकरण रद्द किए जाने के संबंध में आंशिक सूचना उपलब्ध कराई। इससे पता चलता है कि पंजीकरण रद्द करने के संबंध में सूचना अंचलों में ठीक से उपलब्ध नहीं थी।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2022) था; जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023)।

<sup>88</sup> औरंगाबाद, भभुआ, पाटलिपुत्र, पटना उत्तरी एवं पटना विशेष।

**अनुशंसा 7: विभाग अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित करें कि रद्द करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने और वसूली के लिए प्रक्रियाओं में उचित सावधानी बरती जाए।**

### 2.3.9 कार्यबल की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल कार्यकरण के लिए, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित जनशक्ति योजना और इसकी उचित तैनाती आवश्यक है। माल एवं सेवा कर से पूर्व और माल एवं सेवा कर के बाद के दौरान अधिनिर्णयन प्राधिकरण (उप आयुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्य-कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य-कर अधिकारी) के संबंध में वाणिज्य-कर विभाग में स्वीकृत और कार्यशील पदों की संख्या नीचे तालिका 18 में दी गई है।

**तालिका 18**

#### कार्यबल की स्वीकृत और वास्तविक संख्या

विवरण	करदाताओं की संख्या	स्वीकृत बल	वास्तविक बल	रिक्त पद	रिक्त पद का प्रतिशत
माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि (30 जून 2017 तक)	2,33,361	784	421	363	46
माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि (31 मार्च 2022 के तक)	5,89,925	784	484	300	38

(स्रोत: वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना)

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी के संबंध में रिक्त पद 38 प्रतिशत से 46 प्रतिशत के बीच थे। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में करदाताओं की संख्या 2,33,361 से बढ़कर 5,89,925 हो गई, जो माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि की तुलना में 153 प्रतिशत अधिक है। लेकिन, माल एवं सेवा कर से पहले की अवधि में अधिनिर्णयन प्राधिकरणों/अधिकारियों की संख्या 421 से बढ़ कर माल एवं सेवा कर के बाद की अवधि में 484 हो गई, जो केवल 15 प्रतिशत की वृद्धि है इस प्रकार, माल एवं सेवा कर के बाद के काल में उचित अधिकारियों में वृद्धि करदाताओं की संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

### 2.3.10 निष्कर्ष

रिटर्न दाखिल और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से रिटर्न दाखिल की अलग-अलग प्रवृत्ति और निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में "माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न दाखिल पर विभाग की निगरानी" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण द्वारा संचालित था, जिसने जोखिम क्षेत्रों और 2017-18 के लिए दायर माल एवं सेवा कर रिटर्न में नियम-आधारित विचलन और विसंगतियों को उजागर किया था। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा ने दो स्तरों पर राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं (अंचलों) के निरीक्षण कार्यों का आकलन किया; वैश्विक डेटा पृच्छा के माध्यम से डेटा स्तर पर और कार्यात्मक स्तर



पर, जिसमें करदाता अभिलेख तक पहुंचना शामिल था। लेखापरीक्षा नमूने में नौ अंचलों, वैश्विक पृच्छाओं के माध्यम से चुने गए 15 मापदंडों में 423 उच्च मूल्य विसंगतियां और वर्ष 2017-18 के लिए माल एवं सेवा कर रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चुने गए 100 करदाता शामिल थे।

विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के लिए विस्तृत अनुदेश/मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी नहीं की थी। नौ अंचलों की समीक्षा से पता चला है कि रिटर्न दाखिल और करदाता अनुपालन की निगरानी जैसे अंचलों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण अपर्याप्त था और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नहीं था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए 423 उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों में से, विभाग ने 361 मामलों का जवाब दिया। इनमें से 51 प्रतिशत यानी 184 मामले ₹ 2,114.73 करोड़ की अनुपालन कमियां (₹ 1,999.36 करोड़ की बेमेल राशि, ₹ 115.37 करोड़ के राजस्व निहितार्थ और ₹ 6.75 करोड़ की वसूली की गई राशि सहित) के रूप में सामने आए। बेमेल राशि सरकारी खजाने पर राजस्व प्रभाव को इंगित करती है। ब्याज का कम/भुगतान न करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेमेल, गलत आवर्त घोषणाओं और कर के कम भुगतान में अपेक्षाकृत अधिक दर की कमी देखी गई। आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 13 प्रतिशत मामलों में विसंगतियां हुईं और आठ प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई की थी। विभाग ने विसंगतियों के 62 मामलों का जवाब नहीं दिया, जिनमें ₹ 98.08 करोड़ (बेमेल सहित) का जोखिम पहचान किया गया है।

माल एवं सेवा कर रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा ने भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन का सुझाव दिया। शुरुआत में, 100 करदाताओं के नमूने में से 79 मामलों में वित्तीय विवरण, चालान आदि जैसे बारीक आँकड़ा पेश नहीं किए गए थे, जो एक महत्वपूर्ण दायरों की सीमा का संस्थापित करता था। लेखापरीक्षा में ₹ 85.02 करोड़ की अनुपालन कमियां पाई गईं (जिसमें ₹ 71.91 करोड़ की बेमेल राशि, ₹ 12.82 करोड़ का राजस्व निहितार्थ और ₹ 0.29 करोड़ की वसूली गई राशि शामिल है)। मुख्य कारण गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना, गलत आवर्त घोषणाएं, कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का गैर/अल्प भुगतान और कर का कम भुगतान था।

### 2.3.11 सिफारिशों का सारांश

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को इस प्रतिवेदन में सामने लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई समय सीमा समाप्त होने से पहले शुरू करनी चाहिए। रिटर्न दाखिल, करदाताओं के अनुपालन, कर भुगतान पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने के लिए अंचलों में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। विभाग डेटा आँकड़ा प्रविष्टि को रोकने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने और बेहतर जाँच की सुविधा के लिए माल एवं सेवा कर परिषद को माल एवं सेवा कर रिटर्न में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण/सॉफ्ट अलर्ट का प्रस्ताव कर सकता है। विभाग विवरणियों की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया/विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और धारा 65 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठा सकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और राजस्व नुकसान को रोकने के लिए वसूली की जा सके।

## 2.4 लिंगेसी मामले

### 2.4.1 सामग्री की आपूर्ति पर टीडीएस की कटौती न करने के कारण राजस्व की हानि

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के विपत्र से टीडीएस की कटौती न करने के कारण कर देयता की कम स्वीकृति का पता नहीं लगाया जा सका जिसके कारण ₹ 1.77 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।**

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 51 कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान से, जहाँ एक अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कूल मूल्य ₹ दो लाख पचास हजार (करों को छोड़कर) से अधिक हो, सरकारी एजेंसियों, विभागों और स्थानीय अधिकारियों (कटौतीकर्ता) द्वारा एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती को प्रावधित करता है। इस धारा के तहत टीडीएस कटौती के रूप में काटी गई राशि का भुगतान कटौतीकर्ता द्वारा सरकार को उस माह के अंत के 10 दिनों के अंदर किया जाना है जिसमें ऐसी कटौती की गई है।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, के नियम 12(1) एवं 12(2) में प्रावधित है कि किसी भी व्यक्ति की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती करने की आवश्यकता है, उसे माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकरण प्राप्त करना होगा, इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66(1) प्रावधित करता है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसे बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 51 के तहत टीडीएस की कटौती करने की आवश्यकता है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (वाणिज्यिक-कर विभाग को) माल एवं सेवा कर के सामान्य पोर्टल के माध्यम से एक सामान्य रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

बाँका जिले के सभी 11 प्रखंडों<sup>99</sup> के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (नवम्बर 2022) में पाया गया है कि कार्यक्रम अधिकारियों ने न तो खुद को माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत किया था, न ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की गयी आपूर्ति के कारण आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान से टीडीएस की कटौती की थी। लेखापरीक्षा ने आगे, आपूर्ति की गयी सामग्री, मनरेगा कार्यालय से आपूर्तिकर्ता द्वारा एकत्रित माल एवं सेवा कर और आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके माल एवं सेवा कर रिटर्न में स्वीकार किये गये माल एवं सेवा कर के विवरण का सत्यापन किया। यह पाया कि 16 आपूर्तिकर्ताओं ने अपने माल एवं सेवा कर रिटर्न में कर देयता के रूप में मात्र ₹ 1.80 करोड़ स्वीकार किये थे; जबकि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बाँका जिले में मनरेगा के तहत की गयी सामग्री की आपूर्ति पर ₹ 3.57 करोड़ एकत्र किये थे। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 1.77 करोड़ की राशि के राजस्व की हानि हुई, जो कि परिशिष्ट 2.23 में वर्णित है।

<sup>99</sup> अमरपुर, बाँका, बरहट, बेलहर, बौसी, चानंद, ढोरिया, फूलीडुमर, कटोरिया, रजौन और शंभुगंज।

यदि कार्यक्रम अधिकारियों ने खुद को माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत किया होता और माल एवं सेवा कर नियमों के तहत किये गये प्रावधानों के अनुसार टीडीएस की कटौती की होती, तो आपूर्तिकर्ता अपने कर योग्य आवर्त और कर देयता का छिपाव की स्थिति में नहीं होते। इस तरह का छिपाव, इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आयकर की गणना के लिए आय को छिपाने की संभावना का भी संकेत था।

मामला वाणिज्य-कर विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2022)। जवाब में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (दिसम्बर 2022) कि चूँकि मनरेगा की सूचना प्रबंधन प्रणाली में सामग्री आपूर्ति के अभिश्रव पर टीडीएस की कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है, माल एवं सेवा कर के प्रावधान का अनुपालन अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। वाणिज्य-कर विभाग का जवाब अप्राप्त था (नवम्बर 2023 तक)।

